चुनाव की सूली पर देश की प्रतिष्ठा!

महेंद्र मिश्र

नेतृत्व अगर बौना हो तो कोई बड़ा देश भी छोटा हो जाता है। ठीक इसके विपरीत बड़ा नेतृत्व छोटे देश को भी बड़ा बना देता है। भारत-पाक के बीच जारी तनाव और उसके सामने आए नतीजों से यह बात और साफ हो गयी है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की सकुशल घर वापसी का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय नेतृत्व खास कर पीएम मोदी और उनकी पूरी कूटनीतिक जमात सवालों के घेरे में आ गयी है। और आखिरी दिन ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद मिली इस कामयाबी पर कितनी खुशी मनाई जाए और कितना गम। तय कर पाना मुश्किल है। दरअसल नजरिये में दूरदृष्टि और गहराई का होना किसी नेतृत्व की सफलता की पहली शर्त होती है। लेकिन जिस नेतृत्व को चुनाव और बूथ की मजबूती से आगे कुछ दिख ही नहीं रहा हो उससे बहुत ज्यादा की उम्मीद करना भी बेमानी है। एक चुनाव में जीत के लिए किसी देश के वर्षों के मान-सम्मान, उसकी परंपरा और उसके इतिहास को दांव पर लगा देना भला कहां की समझदारी कही जाएगी। देश की कूटनीति सुरक्षा सलाहकार और एंटायर पोलिटिकल साइंस के डिग्रीधारी तय करने लगें तो देश को इसी तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ेगा।

मोदी की राजनीति को समझने वालों ने आज से दो साल पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि चुनाव में जीत न होने की स्थित में उनके लिए किसी गोधरा की जरूरत पड़ेगी। और इस मामले में उनके पास मंदिर और सरहद दो अहम विकल्प होंगे। लाख कोशिशों के बाद मंदिर न चलता देख मोदी को सरहद की शरण में जाना पड़ा। उरी पर हमले के खिलाफ हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और जब

जंग में कत्ल सिपाही होंगे सुर्खुरू जिल्लेइलाही होंगे

- मौज रामपुरी

चुनाव नजदीक आया तो फिर सरकार ने उस पर फिल्म बनवा कर पूरे देश में "हाऊ इज दि जोश" का नया उन्माद खड़ा कर दिया। जो युद्धोन्माद की दिशा में पहला कदम था। कैबिनेट मंत्रियों ने बैठकर फिल्म देखी और फिर तो देश में भक्तों के लिए वो किसी तीर्थ सरीखी बन गयी। लेकिन पुलवामा ने इस पूरे जोश पर पानी फेर दिया। इस घटना के लिए जितना पाकिस्तान और आतंकी जिम्मेदार हैं उससे किसी भी रूप में कम केंद्र नहीं है। सरकार को इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए सीआरपीएफ की एयरलिफ्ट की मांग को गृहमंत्रालय ने क्यों ठुकरायी थी?

8 फरवरी को इंटेलिजेंस की उस रिपोर्ट का उसने क्यों नहीं संज्ञान लिया जिसमें इस तरह के किसी आतंकी हमले की आशंका जतायी गयी थी। और ऊपर से पैरामिलिट्री के जवानों से भरी 78 बसों को बगैर किसी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के कैसे और किसकी इजाजत से छोड़ दिया गया? ये ऐसे सवाल हैं जो अभी भी मुंह बाए खड़े हैं। लेकिन इनका जवाब देने की जगह सरकार ने पाकिस्तान का रोना-रोना शुरू कर दिया। क्योंकि बीजेपी की यही तात्कालिक जरूरत थी। और फिर सब कुछ पार्टी की चुनावी जरूरतों के मुताबिक होना था। इस पूरे गुणा-गणित में न तो देश शामिल था और न ही उसकी परिस्थितियां।

पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को न कोई डोजियर दिया गया। न ही किसी सबूत की बात की गयी बल्कि एकतरफा तरीके से उसके आंतकी ठिकानों पर हमले का फैसला ले लिया गया। लेकिन पीएम मोदी और उनकी टीम को शायद ये नहीं पता कि किसी देश की संप्रभुता पर हमले के क्या मायने होते हैं। जम्मू-कश्मीर के पीओके वाले हिस्से तक एकबारगी सोचा जा सकता है क्योंकि ये विवादित इलाका है और उसके लिए आप कोई भी तर्क और बहाना तलाश कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान के शासन वाले किसी संप्रभु इलाके को अवैध तरीके से छूते हैं बात बिल्कुल दूसरी हो जाती है। एनडब्ल्यूएफपी यानी नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्राविंस में स्थित बालाकोट पर हमले से सरकार ने गेंद पाकिस्तान के पाले में डाल दी।

किसी भी देश के लिए ये उसके आन-बान और शान का मसला बन जाता है। एक देश के तौर पर अपने वजूद को साबित करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। लिहाजा पाकिस्तान ने भी रात के अंधेरे में किए गए इस हमले का दिन में जबाव दिया। जिसका नतीजा उसके एफ-16 लड़ाकू विमान के गिरने और हमारे मिग-21 के धराशायी होने के तौर पर सामने आया। और इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तानी क्षेत्र में पकड़े जाने की घटना ने पूरे खेल की बाजी ही पलट दी। हालांकि शुरू में भारतीय पक्ष द्वारा उसे इग्नोर करने की कोशिश की गयी लेकिन बाद में उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन इस पूरे मसले पर पीएम मोदी की चुप्पी अभी भी एक रहस्य बनी हुयी है।

उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के युद्ध के खिलाफ संबोधन और भारत के साथ शांति वार्ता की पेशकश ने एक मिनट में उन्हें स्टेट्समैन बना दिया। और फिर पाक असेंबली के संयुक्त अधिवेशन में विंग कमांडर अभिनंदन की बगैर शर्त रिहाई ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व के एक नये पायदान पर खड़ा कर दिया। उसके बरख्श पीएम मोदी ने इस दौरान देश की जनता से कभी बातचीत करनी भी जरूरी नहीं समझी। ये बात जरूर है कि उनकी रैलियां नहीं रुकीं और वोट मांगने के क्रम में उन्होंने इशारों में ही सही व्यंग्य और मसखरी ज्यादा और गंभीर नेतृत्व का परिचय कम दिया। और आखिर में तो हद ही हो गयी जब उन्होंने पायलट की रिहाई की सूचना पर ये कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया अभी ये रिहर्सल था और अब असली करना बाकी है।

हालांकि सरकार पूरे मामले को इसी रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है कि वो किसी समझौते में नहीं गयी और दबाव में पाकिस्तान को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन इसके पीछे की सचाई भी अब किसी से छुपी नहीं है। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि शुरू से लेकर आखिरी तक पर्दे के पीछे से ट्रंप काम कर रहे थे। यह उसी समय स्पष्ट हो चुका था जब ट्रंप ने कहा था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और आखिर में उपसंहार भी इमरान की घोषणा से 6 घंटे पहले उन्होंने ही यह कहकर किया कि भारत और पाकिस्तान से आज कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी।

इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि मोदी अमेरिका की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। और अब चाहे जितनी भी बात कर लें अमेरिका की इच्छा के बगैर एक कदम भी उठाना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान आगे और लड़ाई न करने का जो वादा मोदी से चाहते थे उसको उनकी तरफ से ट्रंप ने दे दिया है। देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि अभी तक हम कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को खारिज कर देते थे लेकिन आज हमें दोनों देशों के बीच के लिए उसे स्वीकार करना पड़ रहा है।

वाह! मोदी जी वाह! 46 करोड़ मज़दूरों के पेंशन के लिए 500 करोड़ रु. और गाय बचाने के लिए 750 करोड़ रुपये?

मोदी सरकार का बहुप्रचारित छठा, अंतरिम और साथ ही अंतिम बजट एक फरवरी को पेश हुआ।

लेकिन इस बजट में बहुतायत असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों किसानों के लिए धोखे से ज्यादा कुछ नहीं मिला। ये कहना है सीटू के जनरल सेक्रेटरी तपन सेन का।

पांच फरवरी को नीमराना में डाईकिन मज़दूरों की एक सभा में आए तपन सेन ने वर्कर्स यूनिटी से कहा कि इस सरकार की नजर में ग़रीब और मज़दूर गाय से भी गए गुजरे हैं।

उन्होंने कहा, "ये बजट दिखाता है कि एक सरकार कितनी नीचे गिर सकती है?"

वो कहते हैं, "इससे पहले मोदी सरकार पांच बजट पेश कर चुकी है लेकिन उसे अभी तक मज़दूरों किसानों की याद नहीं आई?"

ये बजट नहीं चुनावी घोषणा है?

तपन सेन के मुताबिक, "अब जबकि उसका कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है और वो जानती है कि इसे पूरा करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी, क्योंकि चुनाव बाद कौन सी सरकार आएगी ये निश्चित नहीं है। तो उसने ढेरों ऐलान कर दिए।"

उन्होंने कहा कि 46 करोड़ मज़दूरों के लिए पेंशन के मद में दिया 500 करोड़ रु. जबकि गाय बचाने के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किया। इसी से पता चलता है कि मोदी सरकार का मज़दूरों से कैसा प्रेम है?

जबकि यही ग़रीब असंगठित क्षेत्र का मज़दूर देश की 65 प्रतिशत जीडीपी पैदा करता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को सम्मान निधि के नाम पर 6000 रुपये सालाना देने की घोषणा की।

किसानों का सम्मान या अपमान?

लेकिन ये सम्मान या अपमान? क्योंकि निधि 3.5 रुपये प्रति दिन बैठती है।

उन्होंने कहा कि देश के लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों का अपमान है।

उनका कहना था कि सरकार का बजट चुनावी जुमला है, वो जानती है उसे लागू नहीं करना है और इसकी हर लाइन इन्हीं घिनौनी चालों से सनी हुई है।

बेरोज़गारी दर के मामले में देश सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गया है लेकिन इसका जिक्र तक नहीं है, उल्टे बेरोज़गारों को रोज़गार देने वाला बताया जा रहा है।

वो पूछते हैं कि ये सरकार किसका मज़ाक उड़ा रही है, किसको बेवकूफ बना रही है?

राजकुमार बडजात्या का जाना !

हिंदी सिनेमा में मानवीय और स्वस्थ पारिवारिक मूल्यों की फिल्मों को बढ़ावा देने में राजश्री प्रोडक्शन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक फिल्म निर्माण कंपनी के तौर पर ताराचंद बडजात्या ने 1962 में इसकी स्थापना की थी। अपनी आरंभिक फिल्मों – आरती, दोस्ती, तकदीर, जीवन मृत्यु और उपहार से देशव्यापी चर्चा में आए इस प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी 1972 में राजकुमार बडजात्या ने संभाली और स्वस्थ पारिवारिक फिल्मों की परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि शिखर तक ले गए। हिंदी सिनेमा का सातवां दशक मुख्यत: एक्शन फिल्मों का दौर था जब हिंदी फिल्मों के कथ्य और तकनीक में जबरदस्त बदलाव आए थे। राजकुमार बडजात्या ने बदलाव के इस दौर में भी सार्थक सिनेमा का दामन नहीं छोड़ा और 'पिया का घर', 'सौदागर', 'गीत गाता चल', 'तपस्या', 'चितचोर', 'पहेली', 'दुल्हन वही जो पिया मन भाए', 'अंखियों के झरोखे से', 'सुनयना', 'सावन को आने दो', 'नदिया के पार, 'अबोध' जैसी साफ सुथरी फिल्मों का निर्माण करते रहे।

आठवे दशक में विडियो के आतंक से सिनेमा में आई बड़ी मंदी के कारण कई फिल्मों के असफल होने की वजह से राजश्री प्रोडक्शन बंद होने के कगार पर था। तब उन्होंने अपने पुत्र सूरज बडजात्या के निर्देशन में 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी सुपरहिट फिल्में बनाकर सिनेमा के दर्शकों को एक बार फिर थिएटर तक खींच लाने में बड़ा योगदान दिया। यह सिलसिला 'हम साथ साथ हैं', 'विवाह' और 'प्रेम रतन धन पायो' तक जारी रहा। इसी साल बनी 'हम चार' उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। राजकुमार जी को फिल्म 'अबोध' में माधुरी दीक्षित को ब्रेक देने और 'मैंने प्यार किया' तथा 'हम आपके हैं कौन' से सलमान को स्थापित करने और स्टारडम दिलाने का श्रेय जाता है। हिंदी की स्वस्थ पारिवारिक सिनेमा के झंडाबरदार स्वर्गीय राजकुमार बडजात्या को हार्दिक श्रद्धांजलि !

मलाला ने इंडिया-पाकिस्तान रिश्तों पर जो बात कह दी, वो बड़े-बड़े नहीं कह पाए

उपासना

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखकर पाकिस्तानी कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफ़ज़ई ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से विवाद को खत्म करने के ट्विटर पर एक फोटो शेयर करके आग्रह किया है. मलाला ने कहा है कि दुनिया को एक और युद्ध की जरूरत नहीं है.

"एक नोबेल विजेता, यूएन मैसेंजर ऑफ पीस, पाकिस्तान की एक नागरिक और एक छात्रा होने के नाते मैं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से परेशान हूं- और उन लोगों के लिए चिंतित हूं जो सीमा के दोनों तरफ रहते हैं. युद्ध के खतरे को जानने वाले इस बात से सहमत होंगे कि प्रतिशोध और बदला लेना कभी भी सही जवाब नहीं होता है- एक बार शुरू हो जाए तो खत्म करना मुश्किल होता है. लाखों लोग आज भी चल रहे युद्धों के कारण पीड़ित हैं- हमें एक और नहीं चाहिए. दुनिया इस समय उन सभी पीड़ित लोगों की देखभाल भी करने में सक्षम नहीं है.

मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करती हूं कि इस मुश्किल समय में सच्ची लीडरशिप दिखाएं. साथ बैठें, हाथ मिलाएं ताकि मौजूदा तनाव खत्म हो सके. और लंबे वक्त से चलते आ रहे कश्मीर के मसले का हल निकल सके. मैं दुनिया से गुजारिश करती हूं कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत पर अपना समर्थन दें जिससे कि लोगों की जिदगियां और घर उजड़ने से बच सकें.

दोनों देशों की जनता जानती है कि आतंकवाद, गरीबी, अशिक्षा और बीमारियां उनकी दुश्मन हैं. न कि ये दोनों मुल्क आपस में दुश्मन हैं."